इकाई 1 लोक नीतिः परिभाषा, प्रकृति, महत्व और प्रकार

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 लोक नीति की परिभाषा

1.3 लोक नीति की प्रकृति

1.4 लोक नीति का महत्व और भूमिका

- 1.4.1 सैद्धान्तिक और वैज्ञानिक कारक
- 1.4.2 राजनीतिक और प्रशासनिक कारण
- 1.4.3 आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए शक्तिशाली दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण
- 1.4.4 भविष्य निर्माण के साधन

1.5 नीति के प्रकार

- 1.5.1 वितरणात्मक नीतियाँ
- 1.5.2 पुनर्वितरणात्मक नीतियाँ
- 1.5.3 विनियामक नीतियाँ
- 1.5.4 सांविधानिक नीति मुद्दे
- 1.5.5 विरोध नीति मुद्दे
- 1.5.6 सौदेबाज़ी के नीति मुद्दे

1.6 निष्कर्ष

1.7 शब्दावली

1.8 संदर्भ लेख

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- लोक नीति के अर्थ तथा उसकी प्रकृति को समझ सकेंगे;
- वैष्वीकरण विश्व में लोक नीति के महत्व का वर्णन कर सकेंगे; और
- लोक नीति के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोक नीति के अध्ययन ने पिछली शताब्दी के द्वितीय उत्तरार्ध के दौरान महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है। हालाँकि लोक नीति के कुछ लेखक यह सुझाव देते हैं कि आधुनिक नीति का अध्ययन सन् 1920 के दशक से आरंभ हुआ। इसके साथ ही पुरातन साहित्य जिसमें कि नीति के अध्ययन की स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी है जबकि विशिष्ट नीति विज्ञान के विकास के लिए हैरोल्ड लास्वेल के लेखन कार्य के माध्यम से सन् 1950 से आरंभ होता है (लर्नर और लास्वेल (1951)। इसलिए यह निष्पक्ष तर्क दिया जा सकता है कि लोक नीति का शैक्षणिक रूप में प्रयोग करना पिछली शताब्दी के मध्य से अर्जित किया और अनेक संघर्शों के पश्चात् इसने एक विषय के रूप में अपना स्थान अर्जित किया। सरकार की प्रक्रिया का अध्ययन करने के रूप में, उसके द्वारा नीति–निर्माण के कार्य अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण घटित सम्मिलित हैं जैसे कि राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा व्यापार

प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित हैं। इसके त्वरित विकास के सम्बन्ध में बहुत सारे अनुसंधानकर्त्ताओं, शैक्षिकगणों तथा इसको अभ्यास व व्यवहार में लाने वाले विद्वान मानते हैं कि यह क्षेत्र इतना अधिक विस्तारित और व्यापक हो चुका है कि इसको संभालना अत्यंत ही कठिन हो रहा है। विषय शैक्षिक परम्परागत सीमा रेखाओं को करते हुए या उसे पार करते हुए लोक नीति के विषय में सम्मिलित होना चाहते हैं। वास्तव में, इसकी अन्तर–विषयी जो प्रकृति है, वही इस लोक नीति को दिलचस्प तथा सिद्धान्तों को व्यापक रूप से प्रोत्साहित और उनकी उत्तेजित करती है।

थॉमस डाई के अनुसार, पहले लोक नीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अनुसंधान कर्त्ताओं और विद्यार्थियों के द्वारा प्राधिकृत प्रमुखता दी जाती थी जोकि व्यापकता से संस्थागत संरचना तथा सरकार की दार्शनिकता और न्यायसंगत तर्कों पर केन्द्रित रही है। प्रायः नीतियों पर उनको बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था। राजनीति विज्ञान कुछ हद तक, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के प्रयासों में उनकी सफलता के सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और समूहों की गतिविधियों के साथ अपने विषय सीमा के अंतर्गत ही विषय का विस्तारित अध्ययन करते थे। यह बहुत ही कठिनता से उन संस्थाओं की भूमिका को मान्यता प्रदान करते थे जोकि नीति–निर्माण को एक मुख्य विषय के रूप में देखते हुए इसको प्रमुख विषय बनाने की दिशा में अपनी भूमिका का निर्वाह करते थे। यद्यपि लोक नीति राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है। थॉमस डाई इसके अतिरिक्त यह मानते हैं कि देर से सही राजनीति विज्ञान का ध्यान लोक नीति की ओर केन्द्रित हो गया है – क्योंकि इसका कार्य "सरकार की गतिविधियों के कारणों और उनके परिणामों का चित्रण या वर्णन और स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में होता है।" जबकि राजनीति विज्ञान की प्रक्रिया, सम्बन्धों पर केन्द्रित होती है जोकि लोक नीतियों के निर्माण कार्यों में व्यापक वृद्धि हो गई है, इसलिए लोक प्रशासन के अधिकतर विद्यार्थी लोक सेवकों या लोक प्रशासकों के कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं क्योंकि ये लोग नीति–निर्माण और उनको साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लोक प्रशासन का अध्ययन भी नीतियों के कार्यान्वयन में लगे हुए सम्बन्धित रचनातंत्र पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। यह लोक प्राधिकारियों के संगठनों से सम्बन्धित मुद्दों को ध्यान में लाता है। लोक सेवकों के व्यवहारों का आंकलन करता है और संसाधनों के आबंटन, प्रशासन तथा पुनर्रीक्षण की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार के एक दृष्टिकोण से नीतियों के निर्माण व सूत्रबद्ध करने के तरीकों को निश्चित करना बहुत ही कठिन कार्य है, यद्यपि, यह सामान्यतया कहा जाता है कि नीतियों के कार्यान्वयन के अनुभवों के माध्यम से नीतियों की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। परन्तु लोक नीति का विषय देखा जाए तो प्रकृति में लोक प्रशासन से अधिक राजनीतिक विषय है। राजनीति विज्ञान का यह प्रयास है कि लोक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाए परन्तु यह लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसकी प्रक्रिया से सम्बन्धित है। वर्तमान में लोक नीति पर किए जाने वाले अध्ययन नीति विश्लेषण और लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा मुख्य रूप से अधिकृत हैं और इनका मानना है कि नीति के विषय, सूत्रबद्ध करने की प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

1.2 लोक नीति की परिभाषा

लोक नीति की संकल्पना पहले से ही यह मानती है कि यह संगठित जीवन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि न तो पूर्ण रूप से निजी है और न ही व्यक्तिगत है, बल्कि यह सामान्य रूप से स्थापित है। चर्चा के लिए मुख्य बिन्दु यह समझना है कि "लोक नीति" के विचार का क्या अर्थ है। लोक नीति का शब्द दो अक्षर समूह से निर्मित होता है लोक और नीति।

लोक विचारः सबसे पहले हमे "लोक" शब्द को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रायः इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं जैसे कि "लोक हित" (जन हित); "लोक क्षेत्र" (सार्वजनिक क्षेत्र), "लोक मत" (जनमत), "लोक स्वास्थ्य" (सार्वजनिक स्वास्थ्य) और इसी तरह के अन्य शब्द इत्यादि। इसलिए, "लोक हित" उन क्षेत्रों में कार्य करता है जिसमें "लोक" का लेबल लगा होता है, इसके विपरीत यह "निजी" क्षेत्र से भी सम्बन्धित होता है। लोक आयाम प्रायः लोक स्वामित्व का अर्थ प्रदान करती है अथवा लोक कार्यों के लिए नियंत्रण करना होता है। लोक शब्द मानव की सभी गतिविधियों के सभी आयामों में सम्मिलित होता है जिसमें सरकार के हस्तक्षेप अथवा सामाजिक विनियम की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह विवाद हमेशा ही बना रहता है कि "लोक" और "निजी" के बीच कि यह दोनों क्या हैं?

यह तर्क दिया जाता है कि लोक प्रशासन का उद्‌गम राज्य के एक साधन के रूप में हुआ है, निजी हितों के संरक्षण के स्थान पर लोक हितों को सुरक्षित रखता है। जबकि राजनीतिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि निजी और लोक हितों को केवल बाज़ार के माध्यम से ही संतुलित किया जा सकता है, नव वैष्वीकरण इस विश्वास पर आधारित है कि लोक प्रशासन लोक हितों को उन्नत करने के लिए और अधिक युक्तिसंगत साधन है। मैक्स वेबर का कहना है कि नौकरशाही का उद्‌गम और विकास औद्योगिक समाज में युक्तिकरण की प्रक्रिया के कारण हुआ है। नागरिक सेवक या लोक सेवक युक्तिसंगत कार्यकारी होते हैं जो इन ही सीमाओं में सीमित रहते हैं कि उनका कार्य केवल चुने हुए कार्यकर्त्ताओं की इच्छाओं या उनके आदेशों का पालन करना है। इसलिए लोक नौकरशाही अलग थी, जो मौजूदा निजी क्षेत्र से भिन्न हैं, क्योंकि इनका कार्य लोक हितों की सेवा करना और उनको उन्नत करना है। यह विचार बिन्दु युक्तिसंगत पर आधारित है कि लोक हितों को सुरक्षित करे। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् बहुत ही प्रचलित हो गया है। इसके अतिरिक्त लोक और निजी क्षेत्र के बीच जो अन्तर था वह लोक क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक सुधार होने के कारण यह अब धुंधला हो गया है। इसके परिणामस्वरूप यह दोनों क्षेत्र एक–दूसरे पर आच्छादित हो गए हैं और दोनों स्वतंत्र श्रेणी जो अच्छी तरह से परिभाषित की गई थी वह लगभग समाप्त हो गई है।

नीति का विचारः "लोक" के विचार की तरह से ही "नीति" को भी स्पष्टता से परिभाषित नहीं किया गया है। नीति के और अन्य नाम भी हैं जैसे कि अन्य चीजों के होते हैं, जैसे "कार्य करने के लिए मार्गदर्शन" इसके रूप निम्न में सम्मिलित हैंः

- प्राधिकारवादी निर्णय
- सिद्धान्त या एक नियम
- कार्य की सुप्रयोजन की दिशा या विषय
- निश्चित निर्णय की अभिव्यक्ति
- सरकार के कार्य

दुर्भाग्य से नीति शब्द की परिभाषा विभिन्न लेखकों ने लोक नीति के रूप में अलग–अलग तरह दी हैं। डेविड ईस्टॉन नीति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि यह राजनीतिक व्यवस्था के "परिणाम" के रूप में व्यक्त करती है और लोक नीति को सम्पूर्ण समाज के लिए मूल्यों को प्राधिकार के द्वारा आबंटन का नाम देती हैं (ईस्टॉन, 1953ः 129)। लोक नीति को हेनरी परिभाषित करते हैं कि "सरकार के द्वारा अपनाए गए और लागू किए गए कार्य विधि का नाम है" (हेनरी, 2012ः 342)। एंडरसन का सुझाव है कि नीति को "कार्य की प्रयोजन विधि" के रूप में लेना चाहिए जोकि समस्याओं अथवा सम्बन्धित मामलों से निटपने के लिए अभिकर्त्ता या अभिकर्त्ताओं के द्वारा लिए गए निर्णयों से सम्बन्धित है (एंडरसन, 1975ः 3)।

डाई का मानना है कि "लोक नीति सरकार के द्वारा निश्चित की गई प्रक्रिया है कि क्या उसे करना है और क्या उसे नहीं करना है।" इसी प्रकार से लाइनब्रेरी कहते हैं कि "क्या सरकार को करना है और क्या नहीं करना है – जिनका सम्बन्ध उनके नागरिकों से होता है" (लाइनब्रेरी, 1977 : 2)। पार्सन्स के लिए यह "नीति को परिभाषित करने का प्रयास तथा कार्य करने के लिए या कार्य न करने के लिए युक्तिसंगत आधार की संरचना है।" (पार्सन्स, 1975 : 14)। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि "नीति" किए जाने वाले कार्यों की प्रयोजन विधि या प्रक्रिया है अथवा जो लोग सत्ता में हैं, उनके द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, लक्ष्य या उद्देश्यों को लागू करने की प्रक्रिया मात्र है। इसमें यह भी सम्मिलित कर लेना चाहिए कि लोक नीतियाँ वे होती हैं जिन्हें सरकार के निकायों और उनके अधिकार/कर्मचारियों के द्वारा अपनाया और लागू किया जाता है।

1.3 लोक नीति की प्रकृति

लोक नीति का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है (यहाँ तक कि यदि यह विचार ग़ैर–सरकारी दबाव समूहों द्वारा आएँ अथवा राजनीतिक दलों की ओर से आएँ) जोकि लोक समस्याओं की अनुक्रिया में होते हैं, परन्तु इनको सरकारी और ग़ैर–सरकारी दनों के अभिकर्त्ताओं द्वारा लागू किया जाता है। इस लोक नीति को समझने के लिए इसकी प्रकृति को समझना बहुत अनिवार्य है। एक नीति किसी भी प्रकार की हो सकती है जैसे कि सामान्य या विशिष्ट, व्यापक या संकुचित, सरल अथवा जटिल, सार्वजनिक या निजी, लिखित या अलिखित, स्पष्ट या अस्पष्ट, विवेकाधीन या ग़ैर–विवेकाधीन, विस्तृत और गुणात्मक या मात्रात्मक हो सकती है। लोक नीति को समझने के लिए यह एक कला है और इसी प्रकार यह एक कौशल भी है। यह कला इसलिए है कि सामाजिक समस्याओं की पहचान करने के लिए अंतर्दृष्टि और रचनात्मक होती है, लोक नीतियाँ उपायों के रूप में होती है। जो लोगों को नश्ट कर सकती हैं और इन नीतियों के परिणामस्वरूप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में यह नीतियाँ उनका नेतृत्व कर सकती हैं और उनकी समस्याओं का हल निकाल सकती हैं।

लोक नीतियाँ एक कौशल होती हैं, क्योंकि इन कार्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञान की कुछ जानकारियाँ अवश्य होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो लोक नीति पर बल दे रहे हैं (सरकारी नीतियाँ) यह सरकारी नीतियाँ होती हैं जो सरकार द्वारा "कार्य करने के लिए मार्गदर्शक" के रूप में चुनी जाती हैं। हालाँकि, विशिष्ट या निश्चित के स्थान पर कुछ नीतियाँ को अस्पष्टता या दोषपूर्ण परस्पर विरोधी होने के कारण हानि उठानी पड़ सकती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपरिवर्तनीय नीतियों से पता लगता है कि अपनी सभी गतिविधियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त सरकार बहुत कम बनाती हैं। प्रायः महत्वपूर्ण नीतियों को बहुत ही स्पष्टता से तैयार किया जाता है जहाँ पर कानून, नियम–विनियम या योजना और इस तरह की नीतियाँ सम्मिलित होती हैं। भारत जैसे देश का उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों के द्वारा नीतियों को स्पष्ट कर सकता है तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों की नई तरह से व्याख्या भी कर सकता है जिसके कारण नई नीति का निर्माण किया जा सकता है। न्यायिक निर्णय भी नीतियों के विवरण हो सकते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है।

जैसा कि हम पहले बता चुके हें कि लोक नीतियाँ बहुत विस्तृत या अत्यधिक सामान्य हो सकती हैं और हमेशा आवश्यक नहीं हैं कि वे एक–दूसरे के समान रूप से हों। उपद्रव या अषांति के वातावरण में सरकारी विभाग बिना किसी विशिष्ट नीति के संदर्भ को लिए बिना तुरंत कार्यवाही के दौरान नई नीति बना लेते हैं। कभी–कभी राजनीतिक स्वार्थ साधना या

किसी अन्य कारणों से सरकार उसको पूरा करने की इच्छा न रखते हुए नई नीतियों की घोषणा कर देती है। इसलिए यह संभव हो सकता है कि बिना नीति–निर्माण के भी कार्य किया जा सकता है और बिना किसी कार्य करने की इच्छा होते हुए भी नीति बनाई जा सकती है। लोक नीतियाँ क्योंकि "लोक" प्रकृति की होती हैं जिनको सरकार के प्राधिकारियों के द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया जाता है जोकि उनको शक्ति प्रदत्त करती हैं और कानूनी प्रक्रिया भी प्रदान करती हैं।

एक लोक नीति अपनी विषयवस्तु / विषय के प्रमुख हिस्से को समाहित कर सकती है, जैसे कि विकास नीति जोकि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बनाई गई हों। इसलिए एक अकेली नीति अनेक लिखित दस्तावेजों में पाई जा सकती हैं। एक लोक नीति छोटी भी हो सकती है जो किसी विशिष्ट क्रिया को शामिल करती है, जैसे कि परिवार नियोजन जो लोगों के एक वर्ग या विशिष्ट आयु वर्ग तक ही सीमित हो सकती है अथवा यह व्यापक भी हो सकती है जैसे कि राज्य या देश में सभी लोगों पर लागू हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ नीतियाँ लोगों के विशिष्ट हाषिये पर पड़े लोगों के लिए बनाई गई हों अथवा ऐसे लोगों के लिए हो सकती हैं जोकि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त लोक नीति किसी विशेष क्षेत्र के लिए बनाई गई हों जिसमें नीति के विशेष क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आवास, आर्थिक, सामाजिक और परिवहन के प्रकार की हो सकती हैं। इस स्थापना में इसको और विस्तार देकर अन्तरविषयक परस्पर क्रियाओं के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार के प्रत्येक स्तर पर – केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय – इसमें विशिष्ट अथवा सामान्य नीतियाँ भी हो सकती हैं। तब मेगा नीतियाँ हो सकती हैं जो सभी विशिष्ट लोक प्रशासन के द्वारा अनुकरणीय सामान्य मार्गदर्शन के साथ हो सकती हैं। ड्रॉर के अनुसार, मेगा नीतियाँ अपना कार्य प्रमुख नीति के प्रकार के रूप में करती हैं, यह सुनिश्चित या अनिश्चित नीतियों से अलग होती हैं तथा निर्णायक व निश्चितता के लिए मार्गदर्शन के रूप में सम्पूर्ण लक्ष्यों को स्थापित करने में सम्मिलित होती हैं। व्यापक या विस्तारित नीतियाँ जोकि व्यापक क्षेत्रों में राष्ट्रीय लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करती हैं जैसे कि आर्थिक संवर्धन, पर्यावरण तथा इसी तरह की अन्य, यह सब मेगा नीतियों के उदाहरण हैं (ड्रॉर, 1968)।

समस्या समाधान लोक नीति का प्रमुख प्रश्न या मर्म है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या एक नीति निश्चित रूप से लक्ष्य या उद्देश्य को रखती है। लक्ष्य या उद्देश्य से हमारा यह अभिप्राय है कि यह साधन से साध्य तक की दिशा में जाती है जिसमें किसी कार्य को निर्देशित किया जाता है। जहाँ तक कार्य के लिए नीति एक मार्गदर्शन है, इस लोक नीति के लिए यह आवश्यक है कि उसका लक्ष्य, एक उद्देश्य और प्रयोजन होना आवश्यक होता है। सभी मेगा नीतियाँ, विशेष रूप से प्रयोजनमूलक और लक्ष्य मूलक होती हैं। परन्तु यह विचारणीय विषय है कि सरकार बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य या प्रयोजन के बिना नीति–निर्माण कर सकती है। यह बिना किसी संदर्भ के, कि उसका क्या उद्देश्य अथवा लक्ष्य है, यहाँ तक कि कुछ भी न होने पर यह किसी भी नीति को अपना सकती है। यहाँ तक नीति के लक्ष्य अथवा उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताए जा चुके हैं और नीति भी अपने आपमें व्यापक है और बहुत सामान्य भी है और यह विभिन्न व्याख्याओं में संवेदनशील भी बन सकती है। एक सरकार जानबूझकर व्यापक, अस्थिर या विवादग्रस्त नीतियों को सभी दबाव समूहों, तथा राजनीतिक दलों या लोगों के बहुपक्षीय समूहों की संतुश्टि के लिए इस तरह की नीतियों को अपना सकती है। अतः लोक नीतियों में विविधताओं के कारण यह आष्चर्यजनक विशेषताओं से परिपूर्ण हैं।

जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि प्रयोजनमूलक कार्य विधि ही लोक नीति है। कार्यविधि का स्वरूप सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही तरह से हो सकता है।

सकारात्मक स्वरूप में किसी विशिष्ट समस्या से निपटने के लिए सरकार का कार्य प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। नकारात्मक कार्य विधि व लोक नीति का निर्माण लोक सेवकों द्वारा निर्मित किया जाता है जोकि किसी एक विषय से सम्बन्धित होता है और उस पर कार्रवाई न करने की पहले से उनकी इच्छा होती है।

कभी–कभी लोक नीति कानूनी रूप से बलपूर्वक बनाई जाती हैं जिसको कि नागरिक अधिकार और उचित समझ कर स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, कर का भुगतान करना अनिवार्य होता है यदि व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना हो सकता है, उसको कैद की सजा भी हो सकती है, अथवा दोनों सजाएँ भी एक साथ हो सकती हैं यह कानूनी बल प्रयोग की प्रकृति होती है, इस तरह की लोक नीति निजी संगठनों से लोक संगठनों को अलग करती है उनमें भेद स्थापित करती है। नीतियाँ अन्ततः लाभदायक मानी जाती हैं, इसलिए इनका पक्ष भी लिया जाता है और यदि ये नीतियाँ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं जो ऐसी स्थिति में उनको निरस्त किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा अथवा स्वास्थ्य से सम्बन्धित नीतियाँ होती हैं। इस प्रकार से नीतियों को संशोधित किया जा सकता है और कुछ परिवर्तन करने के बाद लागू करने के लिए उनका विस्तार भी किया जा सकता है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) लोक नीति के अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। विकासशील देशों के लिए लोक नीति की क्या भूमिका होती है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) "लोक नीति से मूल्यों का सत्ता द्वारा आबंटन किया जाता है" (इस्टन)। चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

1.4 लोक नीति का महत्व और भूमिका

लोक नीति सरकार के कार्यों एवं उसकी गतिविधि का महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। यह वह क्षेत्र है जिसमें उन क्षेत्रों का कार्य किया जाता है जिन पर लोक के रूप में चिन्हित किये गये होते है। लोक नीति की संकल्पना में यह पहले से ही माना जाता है कि यह जीवन को प्रभावित करती है जोकि न निजी है और न ही पूरी तरह से व्यक्तिगत परन्तु यह सामान्य

लोगों में निहित होती हैं। इस प्रकार से लोक नीति का महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है जो समाज के घरेलू जीवन की सेवा में कार्य करते हैं। इस लोक नीति के अध्ययन के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जो निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत हैंः

1.4.1 सैद्धान्तिक और वैज्ञानिक कारक

एंडरसन, उदाहरण के लिए तर्क देते हैं कि एक व्यक्ति लोक नीति का अध्ययन इसलिए करता है कि वह और अधिक इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में जान सके, इस विषुद्ध विज्ञान के ज्ञान को जान सकें और इसके व्यवसायी के द्वारा अभिविन्यास करके इसका प्रयोग कर सकें, दोनों ही स्थिति में यह महत्वपूर्ण है। यह एक व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं और नीति निर्णयों के कारणों तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली गतिविधियों की उत्तम समझ पैदा करती हैं। लोक नीति को आप निर्भरता का रूप मान सकते हैं अथवा इसे स्वतंत्रता के रूप में परिवर्तित स्वीकार कर सकते हैं। जब इसके सम्बन्ध में परिवर्ती निर्भरता का विचार होता है तब हमारा ध्यान पर्यावरणात्मक कारकों पर जाता है जो नीति के विषयों को आकार देने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और औद्योगिकीकरण नीति के विषयों को आकार प्रदान करने में सहायता करता है। दूसरी ओर यदि लोक नीति का विचार स्वतंत्र रूप से परिवर्तित है तब हमारा ध्यान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर तुरंत जाएगा। उदाहरण के लिए, आर्थिक नीति का श्रमिक वर्ग पर विशिष्ट प्रभाव क्या पड़ेगा? इस प्रकार के प्रश्नों को उठाने से हम पर्यावरण और लोक नीति के बीच सम्बन्धों को समझ और अधिक उन्नत कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम नीति विश्लेषण के विकास में सहयोग कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं है कि लोक नीति के कारणों तथा इसके परिणामों की समझ को व्यावहारिक सामाजिक समस्याओं के समाधानों के लिए इस वैज्ञानिक जानकारी या इस ज्ञान को लागू करने में हमको सहायता मिलल सकती है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लोक नीति के अध्ययन से किस प्रकार से विशिष्ट लक्ष्यों पर व्यावसायिक परामर्ष द्वारा सहायता प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक व्यावसायिक लोगों का सम्बन्ध है कि वे लोक नीति के सम्बन्ध में अपनी समझ तथा जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् किस प्रकार से सरकारों अथवा लोक प्राधिकारियों को कुछ लाभदायक सुझाव और परामर्ष देने के योग्य बन सकेगें ताकि किस प्रकार से नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन नीतियों को लागू किया जा सके अथवा दी गई नीति के विकास के संचालन में पर्यावरणात्मक कारक किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इन सबके बाद भी यह एक तथ्यात्मक ज्ञान है जिसके द्वारा लोक क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का समाधान इस प्रकार से निकाला जा सकता है, जिसकी जानकारी या अध्ययन में स्वतः ही इसकी पूर्व शर्त होती है।

इन दिनों में, इस तरह के विचारों पर विशेष ध्यान देने से नीति के विश्लेषण में अत्यधिक सहायता मिलती है। इसमें यह विषयवस्तु सम्मिलित है कि नीति के सूत्रबद्ध करने, उसका कार्य पालन तथा उसके मूल्यांकन की सफलता आखिरकार नीति विश्लेषण की सफलता पर निर्भर करती है। सम्पर्क या बातचीत के माध्यम से लोक नीति के विद्यार्थी लोक नीति को सूत्रीकरण तथा कार्यान्वयन की सामूहिक गतिविधियों अवलोकन के माध्यम से सैद्धान्तिक ज्ञान की प्राप्ति करने में सफल होते हैं।

1.4.2 राजनीतिक और प्रशासनिक कारण

लोक नीति का अध्ययन करने का एक कारण राजनीति भी है, जो लोग राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी लोक नीति का अध्ययन करते हैं ताकि उन प्राथमिकताओं

के आधार पर नीति के विकल्पों को उन्नत किया जा सके। यह ज्ञान जिसको वे नीति विश्लेषण के अध्ययन के द्वारा प्राप्त करते हैं, इस तरह के मुद्दे जो प्रशासन की कार्यविधियों में सम्मिलित होते हैं वे सब लोक महत्व के होते हैं तथा मूल्यों को लोक निर्माण के रूपांतरण में बदल देने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विद्यार्थी और विद्वान इस विषय से सम्बन्धित होते हैं कि सरकार को समुचित लोक नीतियों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह उनके चिन्तन का विषय होता है। वे कहते हैं कि विषयों को तत्कालीन तथा राजनीतिक समस्याओं पर "मौन" या "निस्सहाय" नहीं रहना चाहिए तथा उनका यह नैतिक कर्त्तव्य है कि दी गई समस्या पर विशिष्ट प्रतिबद्धता होना चाहिए। उनको किसी भी प्रकार से जिसे वे ठीक समझते हैं उसी तरह से लोक नीतियों की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए विशेषज्ञता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना चाहिए। इस तरह के कदम उठाते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि क्या समुचित रूप से नीतियों का निर्माण किया गया, इस संभावित असहमति का विषय विचार से अलग रखा जाना चाहिए।

1.4.3 आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए शक्तिशाली दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण

लोक नीति जैसा कि हमने विष्लेषित किया है कि यह लोकतान्त्रिक सरकार का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा यह लोगों और उनकी समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है। यह वह क्षेत्र है जिसमें लोक हितों का संरक्षण और उनका विस्तार होता हैं। लोक नीति के मुख्य कार्य और भूमिका समाज को उसके कल्याण तथा भलाई के लिए एक बेहतर स्वरूप प्रदान करना होता है। इसके साथ ही सामाजिक–आर्थिक विकास के क्षेत्र में व्यापक सीमाओं के विस्तार में नीतियों को सूत्रबद्ध किया गया था। अनेक नीतियों को संविधि में परिवर्तित कर दिया गया था जैसे कि औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम 1955 (सन् 1977 में नियमों सहित अधिसूचित किया गया); अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) उन्मूलन अधिनियम, 2016; वन अधिकार अधिनियम, 2016; राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति नीति (1999); व्याभिचार अवैध व्यापार (उन्मूलन) अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित); दहेज उन्मूलन अधिनियम, 1961 (1986 में संशोधित); सती प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1987; बाल विवाह निरोध अधिनियम, 2006 (2007 में संशोधित); महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005; बाल यौन अपराध निरोध अधिनियम एवं नियम, 2012; राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017); राष्ट्रीय युवा नीति (2014); तथा इसकी तरह के अधिनियमों के उदाहरण मौजूद हैं। अभी हाल में केन्द्र सरकार ने 12 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं का बलात्कार करने वाले सज़ायाफ्ता अपराधी को फाँसी (मृत्यु दण्ड) की सजा देने के लिए अध्यादेश जारी किया है (2018)।

हमारे देश में बाहरी आक्रमण और राष्ट्र की अखण्डता की समस्या भी मौजूद थीं। बाहरी वातावरण धमकियों का स्रोत था तथा देश ने अपने बचाव के लिए समुचित नीतियों को विकसित किया था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ आंतरिक चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। क्षेत्रवाद से अनेक विखण्डन की नियत के साथ इसका उफान आया है जिससे निपटने के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया गया है। इसमें केवल रक्षा नीतियों को ही शामिल नहीं किया गया है बल्कि इसी प्रकार से विकेन्द्रीकरण करने का भी प्रयास किया गया है जिसने महाराष्ट्रीय संबद्धता को भी उत्पन्न किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता से लेकर भारत में लोक नीतियों को सूत्रबद्ध इस दृष्टि से किया गया है कि सामाजिक–आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्र की अखण्डता को बनाए रखा जा सके।

1.4.4 भविष्य निर्माण के साधन

लोक नीति एक क्षेत्र के रूप में भविष्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रचनातंत्र है। इसकी पूर्व की शर्तें और समाज की बेहतरी के लिए भविष्य निर्माण से सम्बन्धित है। पूर्वकाल का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वर्तमान नीति व्यवस्था को स्पष्ट करने में सहायता करता है। पूर्वकाल की नीतियाँ वर्तमान और भविष्य की नीतियों में लगातार बनी रहती हैं। लोक नीति का अध्ययन वर्तमान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नीति की समस्याओं को परिभाषित करते समय सहायक सिद्ध होता हैं।

अतः वर्तमान में नीतियों का निर्माण समस्या–समाधान पद्धति के रूप में विचार माना जा सकता है, इसमें यह महसूस किया जाता है कि विकल्पों की परिभाषा शक्ति का सर्वोत्तम साधन या उपाय होता है।

हम वर्तमान प्रवृत्तियों के बर्हिवेशन के द्वारा भविष्य को समझ सकते हैं। भविष्य में कुछ प्रमुख सामाजिक प्रवृत्तियों प्रक्षेपण का विचार इस सम्बन्ध में सहायता कर सकता है। इन उद्देश्यों के लिए आँकड़ों का संग्रह करने को जनसंख्या वृद्धि कर, शिक्षा, सार्वजनिक या लोक स्वास्थ्य और इसी तरह के अन्य विषयों में परिवर्तन करने के लिए इनको सम्मिलित किया जा सकता है। हम इन प्रक्रियाओं को पूर्व घोषणा के द्वारा ले सकते हैं कि एक दशक के पश्चात् यह प्रक्षेपण किस प्रकार के दिखाई देंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोग लोक नीतियों के परिणामों से संबद्ध होने की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

1.5 नीति के प्रकार

नीतियाँ सरकार के कार्यों के घटकों में से एक है। इस भाग में हम वर्णन करेंगे कि किस तरह से, प्रकारों के द्वारा नीतियों को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। लोवी (Lowi) जोर देकर तर्क प्रस्तुत करते हैं कि नीतियों के तीन प्राथमिक प्रकार होते हैंः वितरणात्मक, पुनर्वितरणात्मक और नियामक। लोवी के अनुसार सभी लोक नीतियाँ एक–दूसरे से संबद्ध हैं, ये व्यक्तिगत विकल्प तथा सामाजिक सम्पर्क की खोज में लगी होती हैं।

1.5.1 वितरणात्मक नीतियाँ

सामान्य शब्दों में वितरणात्मक नीतियाँ विशेष हित समूह को लाभ पहुँचाने के लिए नीतियाँ होती हैं अथवा सुपरिभाषित सम्बन्धित लाभार्थियों के लघु समूह के हितों को साधने के लिए होती हैं। वितरणात्मक नीति के उदाहरणों में खाद्य राहत, फार्म अनुदान और समुदाय के कमज़ोर वर्गों से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना, इसी तरह के अन्य हितकारी कार्य इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। किसी भी नीति या योजना जो इसी तरह से बिल्कुल विशिष्ट हो, उसके सम्बन्ध में विधान निर्माण आंषिक प्रशासनिक विवेकपूर्ण निर्णयों को अनुमति प्रदान करता है।

1.5.2 पुनर्वितरणात्मक नीतियाँ

पुनर्वितरणात्मक नीतियों को कार्यों के द्वारा विशेषीकृत किया जाता है", इसमें सम्पत्ति, समर्षद्धि, व्यक्तिगत या नागरिक अधिकार या सामाजिक वर्गों या जातीय समूहों में कुछ अन्य मूल्यवान वस्तुओं का आबंटन जोड़–तोड़ या छल–कपट से करने की इच्छा होती है।" पुनर्वितरणात्मक नीतियों के उदाहरण में अषक्तता या विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के साथ व्यक्तियों को (विकलांग अधिनियम जिसको फरवरी 1996 में लागू किया गया, इसमें

विकलांगता के साथ व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के पक्षों को उन्नत करना व निरोध दोनों को शामिल किया गया है), नागरिक अधिकार (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955) इसमें अस्पष्यता के किसी भी तरह के व्यवहार करने पर सजा का प्रावधान रखा गया है), इसमें सामाजिक अल्पसंख्यकों के लिए निर्धन विद्यालयों को सहायता देने का प्रावधान रखा गया है, इसी तरह के अन्य प्रावधानों को इसमें सम्मिलित किया गया है।

1.5.3 विनियामक नीतियाँ

विनियामक नीतियाँ वे नीतियाँ होती हैं जो व्यवसाय के आचरण के साथ शासित होती हैं। वे विनियमित उद्योगों पर स्तर को अधिरोपित करते हुए प्रत्यक्ष व्यक्ति के व्यवहार को बदलने का प्रयास करती हैं तथा इस तरह से प्रायः अत्यधिक विवादग्रस्त स्थिति पैदा हो जाती है। निजी हितों को प्राप्त करने की दिशा में उनका प्रतिरोध किया जाता है या फिर विनियामक कार्यों के द्वारा उनको लागू करने पर वाद व्यय लगाया जाता है। इस प्रकार के संगठन जैसे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI), भारतीय बार परिशद (Bar Council of India), भारतीय फार्मेसी परिशद (Pharmacy Council of India) और भारतीय नर्सिंग परिशद (Nursing Council of India)। से सब अभिकरण विनियामक अभिकरणों के उदाहरण हैं जो अलग–अलग व्यवसायों के मानकों को बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण करते हैं। इसी तरह से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India - TRAI), भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India - SEBI) और इसी तरह के अन्य अभिकरण विनियामक कार्यकलापों के कार्यों में व्यस्त हैं।

1.5.4 सांविधानिक नीति मुद्दे

बाद में, लोवी (1972) ने एक अन्य प्रकार के मुद्दे को सम्मिलित किया : सांविधानिक नीति मुद्दे – स्थापित किए गए या संस्थाओं का पुनर्गठन करना शामिल है। इनमें से प्रत्येक नीति मुद्दे विभिन्न शक्ति के कार्य क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। हालाँकि, यहाँ पर यह उल्लेख कर देना चाहिए कि लोवी के राजनीतिक नीतियों के कार्यों के रूप में उनके विचारों की आलोचना की गई है जैसे कि सरलता से अधिक प्रणाली विज्ञान के रूप में षंका जाँच की कमी को प्रदर्शित किया गया है (कोब्ब तथा एल्डर, 1972 : 96)।

1.5.5 विरोध नीति मुद्दे

लोवी की नीति के चार प्रकार हैं। कोब्ब तथा एल्डर नीति मुद्दों के वर्गीकरण के विकल्पों को प्रस्तुत करते हैं, यह विषय के स्थान पर विरोध को प्रकट करते हैं। इनके विचार का मुद्दा यह है कि नीतियों में विरोध को पैदा किया जाता है और उसे व्यवस्थित भी किया जाता है। इनके अनुसार दो या इससे अधिक समूहों के बीच स्थितियों या पदों व संसाधनों के वितरण के सम्बन्ध में विरोध पैदा होता है। यह स्थिति के उत्पन्न होने पर जैसे कि (i) स्थितियों या संसाधनों के वितरण में अनुचित या पूर्वाग्रह को अपनाया; (ii) व्यक्तिगत या समूह के लाभ के लिए मुद्दे का निर्माण करना; (iii) ग़ैर–अग्रिम मानव घटनाएँ, प्राकृतिक लोक नीतिएँ, अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष या विरोध, युद्ध और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन इसमें सम्मिलित किए गए हैं।

1.5.6 सौदेबाज़ी के नीति मुद्दे

कुछ अन्य विद्वान हैं जो लागत और लाभ के आधार पर नीति मुद्दों को वर्गीकृत करते हैं। होगवुड और विल्सन लागत और लाभ के आयाम का प्रयोग करते हैं, विभिन्न परिणामों की संभावना, सौदेबाज़ी और विरोध का स्वरूप तथा अन्य विकल्पों की संभावनाओं के विचार का

बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। यह पुनर्वितरण है या मुद्दे को काटना है, इसमें यह विवाद पैदा होगा कि कौन क्या लेगा, कौन अधिक प्राप्त करेगा और कौन कम लेगा। विल्सन के लिए लागत और लाभ को संकेन्द्रित किया जा सकता है अथवा उसे फैलाया जा सकता है। एक मुद्दा जोकि समाज का एक छोटा वर्ग अपने लाभ पर संकेन्द्रित हो सकता है, परन्तु लागत को कौन विस्तारित करेगा यह एक व्यक्ति के लिए अलग प्रकार हो सकता है, इसमें यह है कि "अधिक संख्या को अधिक खुशियाँ मिलें।" हालाँकि इस प्रकार के लागत और लाभों को शामिल करने के प्रकारों में शामिल करने से जटिलताओं तथा तकनीकी ज्ञान के आयामों को अलग कर दिया गया है जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं।

लोवी के नीति के प्रकारों के विचार बहुत ही प्रभावशाली हैं क्योंकि नीतियों के दृष्टिकोण को केवल सरकार के कार्यों के परिणामों तक ही सीमित नहीं रखते है बल्कि वह एक स्वरूप या आकार भी प्रस्तुत करता है और यह आकार या स्वरूप राजनीतिक संघर्ष के परिणामस्वरूप निर्मित होता है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) लोक नीति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) नीतियों के प्रकारों विज्ञान के आधार पर नीति मुद्दों की तीन श्रेणियों को, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

1.6 निष्कर्ष

लोक नीति अध्ययन और व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जाँच के क्षेत्र के रूप में जब से लोक नीति का उद्‌गम हुआ है, इसका सैद्धान्तिक क्षेत्र और अनुप्रयोग करने में व्यापक विस्तार हुआ है। लोक नीति के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में विकास परिदृश्य तथा समकालीन प्रवृत्तियों का परिनिवेशन करता है। लोक नीति सरकार की गतिविधियों के कारणों और उसके परिणामों का विवरण और स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि लोक नीति के स्वरूप के बलों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान के विकास को भी इसमें शामिल किया गया है। लोक नीति का अध्ययन हमें सामाजिक बुराइयों और उसकी कमियों की जानकारी प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करता है जोकि हमें अध्ययन के अंतर्गत इस विषय में प्राप्त होती

है। यह नीतियाँ सामाजिक स्थितियों के परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावों को छोड़ती है। यह राज्य में व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों को एक साथ संगठित भी करती है। किसी एक लोकतान्त्रिक देश की लोक नीतियाँ महत्वपूर्ण युक्तियाँ होती हैं तथा पूर्व काल से भविष्य काल तक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक रचनातंत्र का कार्य भी करता है।

1.7 शब्दावली

पुरातन उदारवाद (Classical Liberalism): सैद्धान्तिक विचारधारा की व्यवस्था है जोकि "वैयक्तिक स्वतंत्रता और स्वामित्व तथा साधनों के रूप में निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण, धन सम्पत्ति तथा खुशियों में सम्पूर्ण सुधार करना और सामाजिक संघर्ष को कम करना है।"

लोक हित अथवा जनहित (Public Interest) : इस शब्द को परिभाषित करना कठिन है, परन्तु यह व्यापक अर्थ प्रदान करता है, यह लोगों की आवश्यकताओं को संदर्भित करता है तथा उसी को लाभ प्राप्त हो जिसके नाम से इस नीति का निर्माण किया गया।

1.8 संदर्भ लेख

Anderson, J.E. (1975). *Policy Making*. New York: Prager.

Cobb, R.W. & Elder, C.D. (1972). *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Dror, Y. (1968). *Public Policy Making Re-examined.* Pennsylvania: Scranton.

Dye, T.R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Easton, D. (1957). An approach to the analysis of political systems. *World Politics*. 9(1).

Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.

Henry, N. (2012). *Public Administration and Public Affairs*. New Delhi: PHI Learning.

Hogwood, B.W. (1987). *From Crises to Complacency: Shaping Public Policy in Britain*. London: Oxford University Press.

Hogwood, B.W. & Gunn, L.A. (1987). *Policy Analysis for the Real World*. London: Oxford University Press.

Lasswell, H. (1951). The Policy Orientation. In Daniel Lerner and Harold D. Lasswell (Eds). *The Policy Sciences: Recent Development in Scope and Method*. Standford: Standford University Press.

Lineberry, R.L. (1977). *American Public Policy, What Government Does and What Difference It Makes*. New York: Harper & Row.

Lowi, T.J. (1972). Four Systems of policy, politics and choice. *Public Administrative Review.* 32(4).

McCool, D.C. (1995). *Public Policy Theories, Models and Concepts*. Englewood, NJ: Prentice Hall.

Parsons, W. (1995). *Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar.

Sahni, P. (1967). *Public Policy: Conceptual Issues*. Delhi: Kitab Mahal.

Wildavsky, A. (1979). *Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis*, Boston: Little, Brown & Company.

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होने चाहिएः

- लोक नीति का अर्थ, परिभाषा और संकल्पना।
- सैद्धान्तिक और वैज्ञानिक कारण
- राजनीतिक और प्रशासनिक कारण
- आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का सुधार करने के लिए शक्तिशाली दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण
- भविष्य निर्माण के लिए एक युक्ति

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होने चाहिएः

- **नीति का विचारः** "लोक" के विचार की तरह से ही "नीति" को भी स्पष्टता से परिभाषित नहीं किया गया है। नीति का नाम अन्य चीजों में भी हैं। "कार्य करने के लिए मार्गदर्शन" यह इसका रूप ले सकती हैः
- प्राधिकारवादी निर्णय
- सिद्धान्त या एक नियम
- प्रयोजनात्मक कार्य विधि
- निश्चित निर्णय की अभिव्यक्ति
- सरकार की कार्रवाई
- "नीति" प्रयोजनात्मक कार्य विधि से ली गई है अथवा जो सत्ता में हैं उनके द्वारा कुछ लक्ष्य या उद्देश्य को लागू करने के लिए अपनाए गए हैं। यह यहाँ पर उल्लेख किया जाना चाहिए कि लोक नीति वे हें जिनको सरकार के निकायों और उनके अधिकारियों द्वारा नीतियों को अपनाया गया हों और उनको लागू किया गया हो।

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होने चाहिएः

- वितरणात्मक नीतियाँ
- पुनर्वितरणात्मक नीतियाँ
- विनियामक नीतियाँ

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होने चाहिएः

- सांविधानिक नीति मुद्दे – उदाहरण सहित
- विरोध नीति मुद्दे – उदाहरण सहित
- सौदेबाज़ी के नीति मुद्दे – उदाहरण सहित